

भारत में कंपनी शासन (वर्ष 1773-1858)

परिचय

- **कंपनी शासन की शुरुआत:** ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्ष 1600 में एक व्यापारिक कंपनी के रूप में स्थापित हुई थी और वर्ष 1765 में एक शासकीय निकाय में बदल गई थी।
- **आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप:** बक्सर की लड़ाई (वर्ष 1764) के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी (राजस्व एकत्र करने का अधिकार) मिला तथा धीरे-धीरे यह भारतीय मामलों में हस्तक्षेप करने लगी।
- **प्राप्त शक्ति द्वारा शोषण:** वर्ष 1765-72 की अवधि में सरकार की व्यवस्था में द्वैत शासन देखा गया जहाँ कंपनी के पास अधिकार तो थे लेकिन कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी जबकि इसके भारतीय प्रतिनिधियों के पास सभी ज़िम्मेदारियाँ थीं लेकिन कोई अधिकार नहीं था। इसका परिणाम नमिनलखिति के रूप में देखा गया:
 - कंपनी के कर्मचारियों के बीच बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार।
 - अत्यधिक राजस्व संग्रह और किसानों का उत्पीड़न।
 - कंपनी का दवाला, जबकि इसके अधिकारी फल-फूल रहे थे।
- **ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया:** व्यवसाय को नश्वरि दशिरा देने के ललरि ब्रिटिश सरकार ने कानूनों में कर्मक वृद्धि के साथ कंपनी को वनरियमति करने का नरिणय लरिया।

ब्रिटिश सरकार द्वारा पेश किये गए अधिनियम

- **रेगुलेटि अधिनियम, 1773:**
 - **अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित:** इस अधिनियम ने कंपनी को भारत में अपनी क्षेत्रीय संपत्ति बनाए रखने की अनुमति दी, लेकिन कंपनी की गतिविधियों और कामकाज को वनरियमति करने की मांग की।
 - **भारतीय मामलों पर नियंत्रण:** इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों पर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया था।
 - **गवर्नर-जनरल का परिचय:** इसने बंगाल के गवर्नर के पद को बदलकर "**बंगाल के गवर्नर-जनरल**" कर दिया।
 - बंगाल में प्रशासन गवर्नर-जनरल और 4 सदस्यों वाली एक परिषद द्वारा चलाया जाना था।
 - **वारेन हेस्टिंग्स** को बंगाल का पहला **गवर्नर-जनरल** बनाया गया था।
 - बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर अब बंगाल के गवर्नर-जनरल के अधीन कार्य करते थे।
 - **सुप्रीम कोर्ट की स्थापना:** बंगाल (कलकत्ता) में एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ ज्यूडिचर की स्थापना की जानी थी, जिसमें अपीलीय क्षेत्राधिकार शामिल थे, जहाँ सभी मामलों के नविरण की मांग की जा सकती थी।
 - इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश शामिल थे।
 - वर्ष 1781 में अधिनियम में संशोधन किया गया था और गवर्नर-जनरल, परिषद तथा सरकार के कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों का नरिवहन करते समय यदरि कृत्तय करते हैं तो उन्हें अधिकार क्षेत्र से छूट प्रदान की गई थी।
- **पटिस इंडिया एक्ट, 1784:**
 - **दोहरी नियंत्रण प्रणाली:** इसने ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण की दोहरी प्रणाली की स्थापना की।
 - कंपनी, राज्य का एक अधीनस्थ विभाग बन गई और भारत में इसके द्वारा अधिकृत क्षेत्रों को 'ब्रिटिश संपत्ति' कहा गया।
 - हालाँकि इसने वाणजिय और दनि-प्रतदिनि के प्रशासन पर नियंत्रण बनाए रखा।
 - **नदिशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड की स्थापना:**
 - नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों पर नियंत्रण रखने के ललरि कंपनी के एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कयिरा गया था। इसमें शामिल थे:
 - राजकोष के चांसलर
 - राज्य का एक सचवि
 - प्रविी काउंसलर के चार सदस्य (कराउन द्वारा नरियुक्त)
 - महत्त्वपूर्ण राजनीतिक मामले, ब्रिटिश सरकार के सीधे संपर्क में तीन नदिशकों (नदिशकों के न्यायालय) की एक गुप्त समरिति के ललरि आरक्षरिति थे।
 - **गवर्नर-जनरल और कमांडर-इन-चीफ:** गवर्नर-जनरल की परिषद को कमांडर-इन-चीफ सहरिति तीन सदस्यों तक सीमरिति कर दयिरा गया था।
 - वर्ष 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर-जनरल और कमांडर-इन-चीफ दोनों की शक्ति प्रदान की गई थी।

◦ यदि वह नरिणय की ज़मिमेदारी लेता है तो उसे परषिद के नरिणय को ओवरराइड करने की अनुमति दी गई थी ।

■ चार्टर अधनियिम, 1793:

- **गवर्नर-जनरल की शक्तियों का वसितार:** इस अधनियिम ने लॉर्ड कार्नवालिस को उनकी परषिद पर जो शक्ति प्रदान की उन्ही शक्तियों का वसितार भवषिय के सभी गवर्नर-जनरलों और प्रेसीडेंसी के गवर्नरों को कथिा गया ।
- **वरषिठ अधिकारियों की नयुक्ति:** गवर्नर-जनरल, गवर्नर और कमांडर-इन-चीफ की नयुक्ति के लयि शाही अनुमोदन अनविरय थ।
- कंपनी के वरषिठ अधिकारियों को बनिा अनुमति के भारत छोडने पर रोक लगा दी गई थी, ऐसा करना इस्तीफे के रूप में माना जाता थ।
- **अधिकारियों का भुगतान:** इसने नरिधारति कथिा कनिथितरण बोर्ड के सदस्यों और उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से भुगतान कथिा जाए (यह वरष 1919 तक जारी रहा) ।
- कंपनी को सालाना 5 लाख पाउंड का भुगतान बरिटिश सरकार को (इसके आवशयक खर्चों का भुगतान करने के बाद) करने के लयि भी कहा गया थ।

■ चार्टर अधनियिम, 1813:

- **अंगरेज व्यापारियों की मांग:** अंगरेज व्यापारियों ने भारतीय व्यापार में हसिसेदारी की मांग की ।
 - यह मांग वषिष रूप से नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय प्रणाली के कारण व्यापार के नुकसान के मद्देनजर की गई थी, जसिने इंग्लैंड को व्यावसायिक रूप से बेहद नुकसान पहुँचाया थ।
- **कंपनी के एकाधिकार का अंत:** इसके द्वारा कंपनी अपने वाणज्यिक एकाधिकार से वंचति हो गई और ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इससे पूर्व क्राउन की तरफ से अधिकार पूर्वक शासन कर रही थी, की शक्तियों में कमी आई ।
 - हालाँकि कंपनी को चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त थ।
- **शक्ति मूल नविसयियों को सहायता:** साहित्य के पुनरुद्धार, वदिवानों, भारतीय मूल नविसयियों के बीच प्रोत्साहन और भारतीयों के मध्य वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ावा देने के लयि सालाना 1,00,000 रुपए की राशि प्रदान की गई ।
- यह शक्ति प्रदान करने की राज्य की ज़मिमेदारी के सदिधांत को स्वीकार करने की दशिा में पहला कदम थ।

चार्टर अधनियिम, 1833:

- **कंपनी की व्यापारिक स्थिति:** कंपनी को प्रदान की गई 20 साल की लीज (चार्टर एक्ट, 1813 के तहत), जसिमें प्रदेशों पर अधिकार एवं राजस्व संग्रह शामिल थ, को आगे बढ़ा दिया गया थ।
 - हालाँकि चीन के साथ और चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया ।
- **यूरोपीय आप्रवासन:** यूरोपीय आप्रवासन और भारत में संपत्ति के अधग्रहण पर सभी प्रतिबंध हटा दिये गए जसिसे भारत में यूरोपीय उपनविसीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ ।
- **भारत के गवर्नर-जनरल का परचिय:** बंगाल के गवर्नर-जनरल को अब 'भारत का गवर्नर-जनरल' बना दिया गया थ।
 - उसे नागरिक और सैन्य मामलों के अधीक्षण, नयितरण और नरिदेशन जैसी कंपनी की सभी शक्तियों दी गई थी ।
 - समस्त राजस्व उसके अधिकार के तहत वसूले जाते थे और खर्च पर भी उसका पूरा नयितरण थ।

वलयिम बेंटिकि भारत के पहले गवर्नर-जनरल बने ।

- **वधिआयोग:** इस अधनियिम के तहत भारतीय कानूनों के समेकन और संहतिाकरण के लयि इसकी स्थापना की गई थी ।
- इसने भारत के लयि गवर्नर-जनरल की परषिद में एक चौथा कॉमन सदस्य जोड़ा, जो एक कानूनी वषिषज्ञ थ।
- लॉर्ड मैकाले चौथे कॉमन सदस्य के रूप में नयुक्ति होने वाले पहले व्यक्ति थे ।
- **चार्टर अधनियिम, 1853:**
 - **कंपनी की व्यापारिक स्थिति:** जब तक संसद कोई और आदेश प्रदान नहीं करती है, तब तक कषेत्रों पर कंपनी का अधिकार जारी रखना थ।
 - सविलि सेवाओं पर कंपनी का संरक्षण भंग कर दिया गया थ; सेवाओं को अब एक प्रतियोगी परीक्षा के जरिये सबके लयि खोल दिया गया थ।
 - **चौथा कॉमन सदस्य:** कानून से जुड़े एक सदस्य को गवर्नर-जनरल की कार्यकारी परषिद का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया ।
 - **भारतीय वधिान परषिद:** भारतीय वधिायकिा में स्थानीय प्रतनिधित्व का प्रावधान कथिा गया थ। इस वधिायी वगि को भारतीय वधिान परषिद के रूप में जाना जाने लगा ।
 - हालाँकि किसी ऐसे कानून की घोषणा के लयि गवर्नर-जनरल की सहमति आवशयक थी जो वधिान परषिद के किसी भी वधिायक को वीटो कर सके ।
- **भारत सरकार अधनियिम, 1858:**
 - **वरष 1857 के वदिरोह के परणाम:** 1857 के वदिरोह ने प्रशासन में कंपनी की सीमा को उजागर कर दिया थ।
 - वदिरोह ने कंपनी द्वारा कबज़ा कथिा गए कषेत्र पर अधिकार के वभिजन की मांग के रूप में अवसर प्रदान कथिा ।
 - **कंपनी के शासन का अंत:** पटिस इंडिया एक्ट द्वारा शुरु की गई दोहरी प्रणाली का अंत हो गया । अब भारत को राज्य के सचवि और 15 सदस्यों की एक परषिद के माध्यम से क्राउन के नाम पर शासति कथिा जाने लगा ।
 - यह परषिद प्रकृतिा में सरिफ सलाहकार थी ।
 - **वायसराय का परचिय:** भारत के गवर्नर-जनरल की उपाधि को वायसराय से बदल दिया गया, जसिने इस पद की प्रतषिठा को बढ़ा दिया ।
 - वायसराय को सीधे बरिटिश सरकार द्वारा नयुक्ति कथिा जाता थ।
 - भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे ।

कंपनी शासन के दौरान गवर्नर-जनरल द्वारा कथिा गए सुधार:

- **लॉर्ड कॉर्नवालिस (गवर्नर-जनरल, वर्ष 1786-93):** वह सविलि सेवाओं को अस्तित्व में लाने और व्यवस्थित करने वाले पहले व्यक्ति थे।
 - उन्होंने ज़िला फौजदारी न्यायालयों को समाप्त कर दिया और कलकत्ता, ढाका, मुर्शदाबाद तथा पटना में सर्कटि अदालतों की स्थापना की।
 - **कॉर्नवालिस कोड:** इस कोड के तहत किये गए कार्य हैं:
 - राजस्व और न्याय प्रशासन का पृथक्करण।
 - यूरोपीय वषियों को भी अधिकार क्षेत्र में लाया गया।
 - सरकारी अधिकारी अपनी आधिकारिक क्षमता में किये गए कार्यों के लिये दीवानी अदालतों में जवाबदेह थे।
 - कानून की संप्रभुता का सिद्धांत स्थापित किया गया।
- **विलियम बेंटिक (गवर्नर-जनरल, वर्ष 1828-33):** उन्होंने चार सर्कटि अदालतों को समाप्त कर दिया और उनके कार्य कलेक्टर को हस्तांतरित कर दिये गए।
 - उच्च प्रांतों के लोगों की सुविधा के लिये इलाहाबाद में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर नजामत अदालत की स्थापना की।
 - अंगरेज़ी भाषा ने अदालतों की आधिकारिक भाषा फारसी का स्थान लिया।
 - इसके अलावा मुकदमा करने वाले को अब अदालतों में फारसी या स्थानीय भाषा का उपयोग करने का विकल्प प्रदान किया गया था।
 - एक नागरिक प्रक्रिया संहिता (वर्ष 1859), एक भारतीय दंड संहिता (वर्ष 1860) और एक आपराधिक प्रक्रिया संहिता (वर्ष 1861) कानूनों के संहिताकरण के परिणामस्वरूप तैयार की गई थी।

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/the-company-rule-in-india-1773-1858>

